भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1831

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

सैटेलाइट आधारित टोल संग्रहण

1831. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित टोल संग्रहण परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) और फास्टैग की तुलना करते हुए लागत विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) टोल प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने में मौसम संबंधी विकृतियों और गोपनीयता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन जैसी चुनौतियों का आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी नहीं। उपग्रह आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण परियोजना वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी क्रियाशील नहीं है।

(ख) जी नहीं। हालांकि, यह आशा की जाती है कि अवरोध मुक्त प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली का उपयोग करके वास्तविक प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा से जुड़ी परिचालन लागत को कम किया जा सकता है और सड़क प्रयोक्ताओं को काफी सुविधा प्रदान की जा सकती है।

(ग) उपग्रह आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली को चालू करने/ वाणिज्यिक रूप से शुरू करने से पहले, इन चुनौतियों का समाधान विशेषज्ञों और संबद्ध हितधारकों के परामर्श से डेटा एन्क्रिप्शन और असंगत डेटा को फिल्टर करने आदि जैसे उपयुक्त तकनीकी उपायों के माध्यम से किया जाएगा।

*****